ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

साइकिल चलानाः एक खेल नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है

रविवारीय, 08 - 14 अगस्त 2021 वर्ष- दो, अंक - 53, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा की दी बधाई

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन अद्भुत रहा। उनकी मेहनत का प्रतिफल है कि भारत को टोक्यो ओलम्पिक में पहला गोल्ड प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि को देश हमेशा याद रखेगा।

मुख्यमंत्री ने झारखंड की दो महिला हॉकी खिलाड़ियों निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रूपये एवं पक्का मकान देने की भी घोषणा की है

सरकारी जमीन से लेकर, नदियो, तालाबों ,ग्रीनलैंड पर अवैध बन रहे मकानों पर सख्ती नहीं वहीं पुरानी रांची के भवनों को तोड़ने की जिद क्यों?

तोड़ने से नहीं संवरेंगे झारखंड के शहर

वरीय संवाददाता

रांची : हाल ही में रांची नगर निगम के नगर आयुक्त ने बड़ा तालाब के पास स्थित सबसे पुराने अस्पतालों में से एक सेवा सदन को तोड़ने का आदेश जारी किया था। सेवा सदन के भवन का नक्शा पास न होने की दलील दी गयी थी। वहीं सेवा सदन का कहना था कि उसने 1980 में आरआरडीए से नक्शा पास करवाया था जिसे वह रांची नगर निगम के सामने प्रस्तुत कर चुका है , पर निगम उसे मानने से ही इनकार कर रहा है। अंततः सेवा सदन नगर निगम के इस फरमान के खिलाफ कोर्ट में गया और कोर्ट ने भवन तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दिया।

सरकार और रांची नगर निगम की ये कवायद प्रारंभ से ही हास्यास्पद और बेतुकी थी। नगर आयुक्त मुकेश कुमार प्रेस कांफ्रेस करके सेवा सदन को अवैध बता तोड़ने की बात कर रहे थे। रांची नगर निगम के इस फरमान पर रांची के लोगों में आक्रोश भी था साथ ही लोगों के मन में यह भरोसा भी कि सरकार इसे नहीं तोड़ पायेगी? वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार के एक मंत्री की पत्नी का होटल भी नदी का अतिक्रमण कर बना हुआ है, जो चर्चा में हैं लोग सवाल पूछने लगे कि क्या सरकार उसे भी तोड़ेगी?

ये दोनो वाकये जनता की नजर में प्रहसन और सरकार, रांची नगर निगम की रंगदारी का नमूना बन कर रह गये। यहां नगर आयुक्त और सरकार की मंशा पर ही जनता संदेह कर रही है। आखिर ये पूरी कवायद वास्तव में रांची को संवारने के लिये है या

सिर्फ परेशान करने की रही है? हालांकि इसके पहले भी एक दो बार रांची में बने बड़े अवैध भवनों को तोड़ने का आदेश जारी हुआ है, पर इस पर अमल आज तक नहीं हुआ।

सेवा सदन या उसके आस पास अपर बाजार के इलाके रांची शहर के वो पुराने इलाके हैं जो तब बसे जब नक्शा पास कराने का प्रावधान नहीं था या नगर निगम का अस्तित्व ही नहीं था। अब इस पुराने बसे हुये इलाके को नगर निगम अपने नियम कानून के डंडे से चलाने लगे तो शहर का एक घना व्यावसायिक और ऐतिहासिक हिस्सा ही उजाड़ना पड़ेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ का कहना है कि पुरानी रांची में हजारो मकान हैं जो बहुत पुराने हैं और बिना नक्शा पास कराये बने हैं। ऐसे मकानों को तोड़ने के बजाय इन्हें रेगुलराइज करने का काम करना चाहिये। सेवा सदन जैसा अस्पताल जो दशकों से लोगों के सेवा कार्य में लगा हुआ है उसे तोड़ने का फरमान कहीं से भी उचित नहीं है।

तस्वीर का दूसरा रूख भी है जिससे सरकार और रांची नगर निगम की मंशा पर संदेह होता है। पुरानी रांची के उन मकानों को तोड़ कर रांची को सुंदर नहीं बनाया जा सकता जो आज से सैकड़ो साल पहले बनाये गये थे इन मकानों को तोड़ देने से ऐसा नहीं है कि रांची में ट्रैफिक जाम, प्रदूषण या पार्किंग समस्या से शहर को मुक्ति मिल जायेगी? क्योंकि ये एक खास छोटे से इलाके को कवर करते हैं, पर सरकार इन्हीं को निशाने पर लिये हुये हैं, जबकि रांची में नये अवैध निर्माणों और अतिक्रमण वाली समस्याओं पर कोई नजर नहीं है।

नक्शा पास कराने के नाम पर सरकारी धोखे में फंस चुके हैं सैकड़ो लोग

रघुवर दास सरकार के समय रांची नगर निगम ने उन मकानों को रेगुलराइज करने की योजना बनायी थी जो बिना नक्शा पास कराये बना लिये गये हैं। इसके लिये नगर निगम ने लोगों से आवेदन मांगे थे। लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि आप का मकान इस योजना में वैध हो जायेगा। सरकार के इस ऑफर पर लोगों को पहले से ही संदेह था यही कारण था कि बहुत कम लोगों ने अपने बने मकान का नक्शा पास कराने का आवेदन दिया। अब ऐसे आवेदनकर्ताओं का नक्शा तो पास नहीं हुआ उल्टे नगर निगम ने उन्हें अवैध मकान बनाने के मामले में लपेट लिया और बिना नक्शा पास के आरोप में फाइन जारी कर दिया।

ऐसे तो पूरी रांची को ही उजाड़ना होगा?

अगर बिना नक्शा पास कराये मकानों को तोड़ने की बात पर वास्तव में अमल किया जाये तो पूरी रांची को ही उजाड़ना पड़ सकता है। रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय का कहना है कि रांची में करीब दो लाख मकान बिना नक्शा पास कराये बनाये हुये हैं , तो क्या सरकार सब को तोड़ेगी? इन्हें तोड़ने के बजाय रेगुलराइज करने का प्लान तैयार करना चाहिये। ऐसी ही राय विधायक सीपी सिंह भी दे चुके है, पर पिछला अनुभव बताता है कि नक्शा पास कराने के लिये आये लोगों को सरकार अवैध निर्माण के आरोप में फंसा दे रही है।

शहर की सूरत और पर्यावरण बिगाड़ने वाले अतिक्रमण पर नजर नहीं

एक तरफ रांची नगर निगम पुराने भवनों को अवैध बता कर तोड़ने का फरमान जारी कर रहा है वहीं हाल में बस रहे उन अवैध बस्तियों अतिक्रमणों की ओर से आंखें मूंदे हुये है जो रांची शहर का पर्यावरण बिगाड़ने से लेकर ट्रैफिक समस्या ,नदियों जलाशयों पर संकट खड़ा कर रहे हैं।

रांची के तकरीबन प्रत्येक नदी के इर्द गिर्द हजारो अवैध मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक बने हुये हैं जो नदी के अस्तित्व पर ही खतरा हैं। ये सभी हाल के कुछ वर्षों के हैं। शहर के बाहर थोड़ा सा निकलते ही ऐसी कोई नदी या जमीन नहीं जो अवैध निर्माण से मुक्त हो, यहां पर सरकार या नगर निगम आंखें मूंद कर सोया हुआ है।

अब अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं खिलाड़ी

अब दुनियाभर के खिलाड़ियों का अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना एक सकारात्मक पक्ष माना जाने लगा है

अमेरिका की सुपरस्टार जिमनास्ट सिमोन बाइल्स, जापान की विख्यात टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका और अब इंग्लैंड के मशहूर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। कहने के लिए ये सभी खिलाड़ी अलग-अलग खेलों के महारथी हैं लेकिन इनमें एक बात सामान्य है। वह है इन सभी खिलाड़ी ने अपने खेल के चरम पर रहते हुए बिना किसी झिझक के यह कहकर खेल आयोजकों और दर्शकों को चौंका दिया कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे खेल से ब्रेक ले रहे हैं।

यहां यह बताना जरूरी है कि इन सभी की मानसिक हालत अलग-अलग कारणों से खराब हुई। जहां नाओमी को मीडिया के नकारात्मक प्रश्नों ने उनकी मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला तो दूसरी ओर सिमोन को अपनी बचपन की बुरी यादों और अच्छे प्रदर्शन के दबाव ने परेशान किया, वहीं स्टोक्स कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए बायोबबल के कारण अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सके। इसलिए उन्होंने अनिश्चतकाल के लिए खेल से ब्रेक ले लिया।

इन तीनों खेल महारथियों में एक सामानता और थी कि अचानक अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण खेलों से अपने को अलग होने के उनके निर्णय को उनके संगी-साथियों सहित आयोजकों ने न केवल समर्थन किया, बल्कि इसे आज की परिस्थितियों में सबसे बड़ी बीमारी तक करार दिया।

टोक्यो ओलंपिक के आयोजन के दौरान आयोजकों पर मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा इतना गर्मा गया है कि आयोजन के बीच में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी से निजात पाने के लिए हेल्पलाइन की घोषणा करने पर बाध्य होना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस समय अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है, लेकिन ओलंपिक में खेलों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते दबाव का ही परिणाम है कि अब आईओसी ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे खिलाड़ियों के लिए दुनियाभर की 70 भाषाओं में हेल्पलाइन शुरू की है और यह हेल्पलाइन ओलंपिक खत्म होने के अगले तीन माह तक जारी रहेगी। आईओसी के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने यह घोषणा ऐसे समय में की जबकि अमेरिका की दिग्गज जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने मनोवैज्ञानिक दबाव से जुड़ी परेशानियों के कारण प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया था। आईओसी के अनुसार यह हेल्पलाइन तात्कालिक सहायता, अल्पकालिक परामर्श, व्यावहारिक सहायता और यदि जरूरी हो तो उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के मामले में मदद प्रदान करेगी।

अनिल अश्विनी शर्मा

राज्य के किसान केसीसी से हो रहे आच्छादित

एक माह में 5,75,761 केसीसी आवेदन प्राप्त

संवाददाता

रांचीः कृषि को झारखंड सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा है। यही कारण है कि खेती-बारी में सहूलियत को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। किसानों को खेतीबारी के दौरान पूंजी की कमी से परेशानी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने तमाम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जोड़ने का विशेष निर्देश दे रखा है।

पूरे राज्य में 30 लाख किसानों का पीएम किसान योजना के तहत निबंधन हुआ था, उन्हें भी केसीसी से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13 लाख केसीसी के चालू एकाउंट हैं, जिनमें 82,421 नये किसानों को केसीसी प्रदान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक जुलाई से 30 जुलाई 2021 तक 5,75,761 केसीसी के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो स्वीकृत होने की प्रक्रिया में हैं। बैंकों को निर्देश मिला है कि वे किसानों को केसीसी जारी करें। गौरतलब है कि सरकार के निर्णय के बाद किसानों का ऋण भी माफ किया गया है।

इससे करीब 1,22,238 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। अबतक ऋण माफी के तहत 600 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं। वर्तमान सरकार अधिक से अधिक किसानों को केसीसी देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। आकंड़ों को देखें तो 2016-17 में 5,57,993 केसीसी, 2017-18 में 3,16,218 केसीसी, 2018-19 में 1,55,953 केसीसी, 2019-20 में 5,01,527 केसीसी और 31 मार्च 2021 तक 8,67,609 केसीसी किसानों को जारी किया गया है।

पांच लाख नये किसानों को केसीसी देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने उन सभी किसानों को केसीसी प्रदान करने का निदेश दिया है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और भूमिहीन कृषक हैं। उक्त आदेश के बाद राज्य के करीब पांच लाख किसानों को केसीसी देने की तैयारी की जा रही है।

किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने का प्रयास

सरकार का प्रयास है कि किसान साहूकारों से कर्ज लेकर उनके चंगुल में न फंसे। इसके लिए सस्ती ब्याज दर पर केसीसी के जरिये किसानों को कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषक मित्र, जनसेवक, अस्सिटेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर (एटीएम), ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (बीटीएम) को अभियान चलाकर किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है।

राज्य के 24 जिलों में केसीसी के लिए 30,93,087 किसानों का निबंधन हुआ था। इनमें से पहले चरण में 30,67,296 किसानों के आवेदन स्वीकृत किए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 69, 259 केसीसी बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया। राज्य के सभी जिलों में शिविर लगाकर केसीसी आवेदन किसानों से प्राप्त किया गया। बोकारो के किसान सबसे अधिक केसीसी से लाभान्वित हुए, इसके बाद पाकुड़, रामगढ़ और गुमला के किसानों ने केसीसी का लाभ लिया। शेष जिलों में भी बड़ी संख्या में किसानों को केसीसी के लाभ से जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना से जोड़ा जाए ताकि वे खेती के लिए जरूरी उपकरण, खाद, बीज आदि खरीद सकें।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से केसीसी जारी किया जा रहा है। सभी जिलों में केसीसी के लिए शिविर का आयोजन हो रहा है। राज्य के सभी योग्य कृषकों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है।

कोरोना : केरल के पांच जिले बढ़ा रहे हैं सिरदर्द

एजेंसियां : कोविड-19 इंडिया डॉट ओआरजी के अनुसार, केरल में पिछले तीन दिन से 22 हजार से अधिक कोविड-19 मामले सामने आ रहे हैं जो देश के कुल मामलों का करीब 50 प्रतिशत है। राज्य में कुल 33,49,365 मामले सामने आए हैं। केरल के एर्नाकुलम जिले में कोविड-19 के सबसे अधिक 4,01,444 सामने आए हैं। 23,00 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद राज्य के मणप्पुरम, कोझिकोड, तिरुअनंतपुरम और थिसूर जिले कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित हैं।सक्रिय मामलों में भी केरल की हिस्सेदारी 1,54,816 है, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में एक लाख की आबादी पर 9,536 लोग वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। केरल की पॉजिटिविटी दर 4.6 प्रतिशत रही है जो पिछले एक हफ्ते में बढ़कर 12.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

महाराष्ट्र बना चिंता का कारण

केरल के बाद महाराष्ट्र सबसे प्रभावित राज्य है। यहां 25 जुलाई के बाद तेजी से मामले बढ़े हैं। 25 जुलाई को यहां 4877 मामले सामने आए। 26 जुलाई को 6258 मामले, 27 जुलाई को 6857 मामले और 29 जुलाई को कुल 7242 नए मामले सामने आए।

भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन के लिए रेलवे ने निविदाएं आमंत्रित की

संवाददाता

कोलकाता :भारतीय रेल ने स्वयं को हरित परिवहन प्रणाली के रूप में बदलने के क्रम में उत्तर रेलवे के 89 किमी. लम्बे सोनीपत-जिंद सेक्शन पर देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन (आईआरओएएफ), भारतीय रेल के हरित ईंधन प्रभाग ने उत्तर रेलवे के सोनीपत-जिंद सेक्शन पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इस प्रयोजन के लिए निविदा-पूर्व दो बैठकें 17अगस्त और 09सितंबर 2021 को निर्धारित की गई हैं। प्रस्ताव देने की तिथि 21.09.2021 तथा टेंडर खुलने की तिथि 05.10.2021 निर्धारित की गई है।

पेरिस वातावरण समझौता 2015 के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लक्ष्य की प्राप्ति की चुनौती को स्वीकार करते हुए तथा रेलवे द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन मिशन के अंतर्गत 2030 तक लक्ष्य प्राप्ति हेतु रेलवे ने सोनीपत-जिंद सेक्शन पर 2 डी.एम.यू. रैक को फ्यूल सेल पावर्ड हाइब्रिड ट्रैक्शन सिस्टम से ट्रेन चलाने का निश्चय किया है। जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन का संचालन किया जाएगा तथा इसके लिए आवश्यक बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

कभी बारिश से निखरने वाली रांची, अब जलमग्न क्यों होने लगी?

कृष्णा मिश्रा

सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बनने का मुख्य उद्देश्य और कारण केवल एक ही था कि उस वक्त के बिहार की राजधानी पटना से निकलने वाली सभी योजनाएं झारखंड के जिलों तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देती थी, जिससे अंत्योदय विकास संभव नहीं था। राज्य बनने के बाद छोटानागपुर पठार वाले क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाने लगा । यानि झारखंड एक पठारी राज्य है और राजधानी रांची एक पहाड़ियों पठारों वाली खुबसूरत नगरी। यहां मॉनसून में बाढ़ और जलजमाव होना अपने आप में एक दुखद आश्चर्य की बात है। आखिर क्यों यहां बारिश में बाढ सी स्थिति पैदा होने लगी है?

एक राज्य के गठन के समय यहां की कुल आबादी 2.69 करोड़ थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 3.30 करोड़ हो गई और वर्तमान समय में लगभग 5 करोड़ (अनुमानित) है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जनसंख्या वृद्धि राज्य गठन के बाद तेजी से हुई ना केवल पहाड़ियों, पठारों, जंगलो बल्कि जलाशयों पर भी अवैध कब्जा करके लोगों ने अपना घर बसाया। विभिन्न जिलों में

तो यह देखा ही गया परंतु राज्य की राजधानी होने के कारण और शहर का मुख्य व्यापारिक केंद्र होने के कारण रांची में बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि हुई बाहर से लोग व्यापार, कामकाज, नौकरी,शिक्षा, पेशा और रोजी-रोटी की तलाश में राजधानी में बसने लगे।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आधार राजधानी में राज्य गठन के बाद लगभग 7 से अधिक जलाशयों पर अतिक्रमण कर उनको नक्शे से गायब कर दिया गया, बड़ी नदियों जैसे स्वर्णरेखा और हरमू जैसी नदिया नाले में तब्दील हो गई वहीं राज्य सरकार और नगर निगम को एक अवसर प्राप्त हो गया इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर बंदरबांट करने का, प्रमुख जलाशयों जैसे हटिया डैम, कांके डैम, गेतलसूद डैम,बड़ा तालाब, जोड़ा तालाब, बटन तालाब, चुटिया तालाब, हटिया तालाब आदि जलाशयों के किनारे सरकारी मुलाजिमों, जमीन दलालों और अफसरों की मिलीभगत से वाटर केचमेंट एरिया कि अवैध रूप से बिक्री शुरू हुई, जल स्तर लगातार बढ़ता रहा और जलाशय सिकुड़ता गया अंततः यह हुआ कि नदियों,ताल-तालाब को ढक कर कंक्रीट का जंगल बसाया गया बेतहाशा विकास के नाम पर लाखों पेड़ों को काट दिए गए और आज भी स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों पेड़ रांची शहर के अंतर्गत काटे जा रहे है। फलस्वरूप यह तो होना ही था कि जिस रांची शहर में आज से 20 से 25 वर्ष पूर्व प्रतिदिन संध्या काल में बारिश रिकॉर्ड दर्ज की जाती थी वहां के लोग पानी के लिए दर-दर भटकते आज देखे जा सकते हैं इसका मुख्य कारण यह है कि पहले जिन जलाशयों में वाटर स्टोरेज की व्यवस्था थी उसे असंतुलित जनसंख्या वृद्धि और विनाशकारी विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया गया और जब रांची में लगातार 3 दिन मात्र 63 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई तो रांची के इलाके जलमग्न हो जाते है किसी मकानों 7 फीट तो किसी बहु मंजिला इमारत की पूरी की पूरी बेसमेंट, वही किसी मुख्य मार्ग पर दर्जनों गाड़ियां डूबी दिखती हैं।

रांचीवासियों के अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण नदियों के रास्तों पर अब अवैध मकानों, दुकानों, अपार्टमेंट, बने गये हैं जिससे करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए जल निकासी प्रणाली बेकार साबित हुयी हैं। तेज बारिश में नदियां उफनती हैं और अपने रास्ते के अवैध मुहल्लों को बाढ़ग्रस्त बना देती हैं। तभी तो कभी बारिश से निखर जाने वाली रांची अब जलमग्न हो जाती है।

छात्रः पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, रांची विवि, रांची

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का सम्मान

ग्रीन रिवोल्ट अपने विषय से हटकर इस बार ओलंपिक में देश की सफलता की खुशियों में शामिल है। इस संपादकीय को लिखते समय ही भारत के लिये नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीत कर देश को खुशियों की सौगात दी है। टोक्यो ओलंपिक भारतीयों के खेल में करवट लेने सरीखा साबित हुआ है और अब यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में भारत ओलंपिक जैसे खेलों में चीन, रूस, अमेरिका, जापान की तरह सफलता अर्जित करेगा।

देश की हार - जीत युद्ध में होती है या खेलों में। चीन , अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में तो खेल में जीत को अपनी राष्ट्रीय अस्मिता तक से जोड़ कर देखा जाता है। वहां जीतना और स्वर्ण पदक प्राप्त करना सिर्फ खेल में जीत नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का मौका माना जाता है। यही कारण है कि वहां एक ओलंपिक के खत्म होते ही दूसरी ओलंपिक के लिये तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। उनके यहां खेलों और खिलाड़ियों पर बेतहाशा खर्च की जाती है।

यह एक सुखद बात है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने भी कई खेलों में विश्व के सामने चुनौतियां पेश की हैं। खास कर महिला खिलाड़ियों ने कई पदक जीत कर देश का मान सम्मान बढ़ाया है।

यह दुखद सत्य है कि क्रिकेट छोड़ खेलों में वैश्विक स्तर पर या ओलंपिक जैसी सर्वोच्च स्पर्द्धा में भारत का प्रदर्शन कभी भी अच्छा नहीं रहा। कई बार तो भारत जैसा बड़ा देश वहां से खाली हाथ ही वापस लौटा है। हम भाग तो लेते रहे, पर देशवासियों के मन में को ई खास उम्मीद कभी नहीं रहती थी। चार दशक पहले हमने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड जीता था जिसका सूखा इस बार हॉकी में कांस्य जीत कर हमने खत्म किया है। वहीं महिलाओं की हॉकी टीम भी पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंची। इसके अलावा सिर्फ किसी खिलाड़ी के व्यक्तिगत जज्बे से हम इक्का दुक्का पदक जीतते आये हैं। लंदन ओलंपिक के बाद से भारत में खेलों का स्तर बहुत सुधरा है और टोक्यो में कई स्पर्द्धाओं में पदक न जीत पाने के बाद भी खिलाड़ियों के चुनौतीपुर्ण प्रदर्शन से यह उम्मीद जगी है कि आगे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि ओलंपिक जैसे खेलों में जीत के बाद तिरंगे का लहराना और राष्ट्रधुन के साथ भारत का नाम होना देशवासियों के लिये सबसे सुखद अनुभूति होती है

दक्षिण एशिया में और बढ़ेगा लू का कहर

लू अथवा हीटवेव तब चलती है जब लंबे समय तक तापमान लगातार कई दिनों तक निर्धारित सीमा से ऊपर होता है। यह आमतौर पर मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हालांकि, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे उष्णकटिबंधीय विकासशील देशों में हीटवेव के बारे में बहुत कम जानकारी है।

वैज्ञानिक लगातार लोगों को इस बारे में जानकारी देते रहे हैं कि दुनिया भर के औसत तापमान में वृद्धि होने के साथ ही भविष्य में चरम घटनाएं और इनकी तीव्रता में वृद्धि होगी। अब इस अध्ययन में बदलती जलवायु में लू (हीटवेव) की आवृत्ति, अवधि और तीव्रता सहित तीन चीजों कि जांच की गई है।

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की पांचवीं आकलन रिपोर्ट में भी सुझाव दिए गए है कि मौसमी और वार्षिक औसत तापमान में वृद्धि मध्य अक्षांशों की तुलना में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में अधिक होने की आशंका है। इसका तात्पर्य है कि दुनिया के अन्य हिस्सो की तुलना में दक्षिण पूर्व एशिया ग्लोबल वार्मिंग से अधिक पीड़ित हो सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में लू (हीटवेव) में किस तरह बदलाव आएगा। शोधकर्ताओं ने कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल के आधार पर, विभिन्न ग्लोबल वार्मिंग स्तरों के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई में लू (हीटवेव) में आने वाले बदलावों का अनुमान लगाया। अध्ययन के अनुसार भविष्य में दक्षिण पूर्व एशिया में गर्मी बढ़ने के साथ-साथ ज्यादा बार हीटवेव आने तथा इसकी अवधि लंबी और अधिक तापमान वाली होने की आशंका जताई गई है। अलग-अलग जगहों के आधार पर लू (हीटवेव) में भी अंतर होगा। समुद्री महाद्वीप और इंडोचीन प्रायद्वीप के बीच ग्लोबल वार्मिंग की प्रतिक्रिया के आधार पर लू (हीटवेव) की विशेषताओं में अतंर हो सकता है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की पांचवीं आकलन रिपोर्ट में भी सुझाव दिए गए है कि मौसमी और वार्षिक औसत तापमान में वृद्धि मध्य अक्षांशों की तुलना में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में अधिक होने की आशंका है। इसका तात्पर्य है कि दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में दक्षिण पूर्व एशिया ग्लोबल वार्मिंग से अधिक पीड़ित हो सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में लू (हीटवेव) में किस तरह बदलाव आएगा।

क्या बजट की कमी से प्रभावित हो रहा है बिहार का बाढ़ राहत अभियान?

पुष्यमित्र

बिहार के 11 जिले के 16 लाख से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, मगर अब तक एक राहत शिविर नहीं खोला गया है। सामुदायिक रसोई से ही काम चलाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस साल एक दिन भी दैनिक बाढ़ प्रतिवेदन को वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं किया, इसे 15 जून के बाद रोज अपलोड किया जाना था। कोरोना टीकाकरण, कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने में आठ हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च होने जा रही है। माना जा रहा है कि इससे सरकार का बाढ़ राहत कार्य प्रभावित हुआ है।

इन दिनों जब हर जगह देश में महाराष्ट्र और दुनिया भर में चीन में आई प्रलयंकारी बाढ़ की चर्चा है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इस साल पहली दफा 23 जुलाई को बाढ़ से जुड़ी रिपोर्ट जारी करते हुए सूचना दी कि राज्य के 11 जिले के 16.61 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और इनमें से 1.10 लाख लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बावजूद इसके विभाग यह मानता है कि इस साल राज्य में बाढ़ जैसी स्थितियां नहीं है, ये छोटी-मोटी घटनाएं हैं। हालांकि बिहार सरकार ने अपने आंकड़े में इस बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या नहीं दी है और न ही यह बताया है कि कितने घरों को नुकसान हुआ मगर यह माना जा सकता है कि बिहार में इस साल की प्रलयंकारी बाढ़ की तुलना महाराष्ट्र और चीन की बाढ़ से नहीं की जा सकती। फिर भी यह आंकड़ा निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है कि विभाग ने 1.10 लाख लोगों को बाढ़ पीड़ित इलाकों से बाहर निकाला है। वे कहां हैं और किस हाल में हैं यह सूचना विभाग ने नहीं दी है। विभाग की 22 जुलाई की फ्लड रिपोर्ट में यह जानकारी है कि सरकार ने अब तक बिहार में एक भी बाढ़ राहत शिविर नहीं खोले हैं। जाहिर सी बात है कि ये 1.10 लाख बाढ़ पीड़ित इन दिनों अपने भरोसे जहां-तहां रह रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक विभाग द्वारा इस वक्त राज्य में 216 सामुदायिक रसोई संचालित हो रही है, जिसमें 1.92 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। यानी बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों को सिर्फ दो वक्त का भोजन उपलब्ध करा देना ही अपनी जिम्मेदारी समझती है। इस कोरोना काल में पीड़ित चाहे जैसे रहें, जहां रहें। दिलचस्प है कि सात जून, 2021 को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश जारी किया था कि बाढ़ राहत अभियान से जुड़े सभी लोगों का ट-ीकाकरण हो, राहत शिविर और सामुदायिक किचेन में कोरोना मानकों का ध्यान रखा जाये।

इस साल बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर तो नहीं ही खोले हैं, बल्कि बाढ़ के मौसम में हर साल जारी होने वाली दैनिक बाढ़ प्रतिवेदन को भी जारी करना बंद कर दिया। पिछले साल तक यह रिपोर्ट खुद विभाग के पोर्टल पर अपलोड हो जाती थी। दो अगस्त तक तो यही स्थिति थी। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के आंकड़ों के छिपा रही है। कोसी नदी के तटबंध पीड़ितों के बीच काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र यादव ने इस आंकड़ों को सार्वजनिक न किये जाने से संबंधित एक सवाल पूछते हुए आरटीआई भी दाखिल किया था, उन्हें जवाब मिला है कि बिहार में दैनिक बाढ़ प्रतिवेदन के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का कोई नियम नहीं है। जबकि इन अनियमितताओं पर लगातार निगाह रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एकलव्य प्रसाद कहते हैं कि किसी भी आपदा से निबटने के लिए आंकड़ों की पारदर्शिता पहली शर्त है, हम जब असम सरकार के बाढ़ से संबंधित आंकड़ों के विवरण देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। पता नहीं क्यों बिहार में सरकार आंकड़ों को उजागर नहीं करना चाहती। राज्य के 11 जिलों के 388 गांवों में फैले बाढ़ के पानी और 16.61 लाख लोगों के पीड़ित होने के बावजूद बिहार सरकार द्वारा एक भी राहत शिविर न खोलना और डेली फ्लड रिपोर्ट को जारी न करना लोगों के मन में कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। यह कयास भी लगाये जाने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से राज्य की माली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए वह बाढ़ पीड़ितों की मदद करने से बच रहा है। विभाग के एक अधिकारी ने नाम पर छापे जाने की शर्त पर इस विलंब की वजह बताते हुए कहा कि ये बहुत छोटे मामले हैं। पिछले साल हमने 22.92 लाख लोगों को मुआवजा बांटा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपादा पीड़ितों की मदद के लिए राशि की कभी कमी नहीं होती। अगर दिक्कत हो तो दूसरे विभागों के हिस्से का बजट हमें दे दिया जाता है। यह सच है कि बिहार में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए अच्छा खासा बजट होता है। इस साल राज्य की आकस्मिकता निधि 8732 करोड़ रुपये की है। इस निधि में से ज्यादातर पैसा आपदा के मामले में खर्च होता है। मगर इस साल इस राशि के तहत कई काम होने हैं। राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन भी इसी पैसे से लगेगा, जिसके लिए 4000 करोड़ रुपये सुरक्षित रखे गये हैं।

केंद्र सरकार से बिहार को नहीं मिलती समुचित सहायता

यह सच है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बिहार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। पिछले साल 11 मई को ही राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र से पैसों की कमी का हवाला देते हुए एडवांस मांग लिया था। जाहिर सी बात है कि तब से अब तक स्थितियां काफी बिगड़ी हैं और राज्य की आय पर भी असर पड़ा है। यह भी सच है कि केंद्र सरकार बिहार की बाढ़ के लिए यहां की सरकारों को समुचित मदद नहीं देती। पिछले साल की बाढ़ से निबटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से 3328 करोड़ रुपये की मांग सितंबर, 2020 में की थी, बाद में उसे संशोधित कर 3634 करोड़ रुपया कर दिया था। मगर केंद्र ने बिहार को सिर्फ 1255 करोड़ रुपये दिये, वह भी फरवरी, 2021 में। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, जब केंद्र द्वारा बिहार के बाढ़ पीड़ितों को समुचित सहायता राशि नहीं दी गयी। 2016 से 2020 के बीच चार बार बिहार ने केंद्र से मदद की मांग की, यह कुल मांग 19683 करोड़ की थी, मगर राज्य को इसके एवज में केंद्र से सिर्फ 3908 करोड़ रुपये मिले। यानी जितने की मांग की गयी उसका सिर्फ 20 फीसदी पैसा मिला। वह भी तब जब केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है। ये तमाम आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि राज्य सरकार कोरोना और लॉकडाउन की वजह से फिलहाल ऐसे आर्थिक संकट से जूझ रही है कि वह फिलहाल बाढ़ पीड़ितों के सवाल को टाल देना चाहती है। हालांकि इस सवाल पर राज्य का कोई अफसर आधिकारिक टिप्पणी देने के लिए तैयार नहीं है।

बाढ़ से निबटने में साढ़े तीन से चार हजार करोड़ होते हैं खर्च

बिहार में बाढ़ और चक्रवात जैसी आपद-ाओं से निबटने में कितनी राशि व्यय होती है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में 2019-20 में इस कार्य के लिए 3539 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, 2017-18 में 4461 करोड़ रुपये। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में इन आंकड़ों का जिक्र है। इस साल बाढ़ राहत के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि का आवंटन हुआ है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, मगर 26 जुलाई, 2021 को बिहार विधानसभा में इस साल का पहला अनुपूरक बजट पेश हुआ जिसमें 600 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए है।

बारिश के पैटर्न में तेजी से हो रहा है बदलाव

वैज्ञानिकों ने कहा है कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नमी वाले क्षेत्रों में बारिश में काफी बदलाव देखने को मिलेगा

भारत में मानसूनी बारिश में काफी बदलाव देखा जा रहा है। जहां एक ओर कुछ राज्यों में अभी तक अनुमान से अधिक बारिश हुई है, वहीं दूसरी ओर बारिश में काफी कमी दिखाई दे रही है। एक नए अध्ययन के मुताबिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने जलवायु मॉडल का उपयोग करके बारिश में हो रहे बदलावों के बारे में पूर्वानुमान लगाया है।

वैज्ञानिकों ने कहा है कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नमी वाले क्षेत्रों में बारिश में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा की सतही हवा के तापमान में 1 से 3 फीसदी प्रति डिग्री की वृद्धि हो रही हैं। जिससे शुष्क और नमी वाली स्थितियों के बीच काफी उतार-चढ़ाव आएंगे। यह अध्ययन चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (सीएएस) के अगुवाई में किया गया है। यह सर्वविदित है कि अधिक बारिश होने से बाढ़ आती है और कम होने से सूखा पड़ता है। शोधकर्ताओं ने दशकों पहले यह पता लगा लिया था कि ग्लोबल वार्मिंग ने औसतन बारिश में वृद्धि की है। यह वृद्धि एक निश्चित समय पर कैसे होती है यह बहुत मायने रखता है। साल भर में समान रूप से होने वाली वार्षिक बारिश में 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यह एक सप्ताह या एक दिन में होती है, तो यह तबाही मचा सकती है।

वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने इस अध्ययन में अत्याधुनिक जलवायु मॉडल सिमुलेशन का उपयोग किया है। जो हर रोज से लेकर कई वर्षों तक के समय के पैमाने पर बारिश में होने वाले बदलाव की वृद्धि पर प्रकाश डालता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि भविष्य में दुनिया भर में तापमान बढ़ेगा, जलवायु संबंधी नमी वाले इलाके - उष्णकटिबंधीय, मानसूनी इलाकों और मध्य से उच्च अक्षांशों सहित न केवल बहुत नमी वाले हो जाएंगे, बल्कि नमी और सूखे वाली स्थितियों में भी काफी बदलाव होगा। अध्ययनकर्ता झोउ तियानजुन ने कहा जैसे-जैसे जलवायु गर्म होती है, नमी वाले इलाके आमतौर पर अधिक नमी वाले हो जाते हैं और शुष्क क्षेत्र सूख जाते हैं। औसत वर्षा परिवर्तन के इस तरह के वैश्विक पैटर्न को अक्सर नमी में लगातार बढ़ोतरी होने के रूप में वर्णित किया जाता है। वर्षा में हो रहे बदलाव के वैश्विक पैटर्न में नमी में लगातार बढ़ोतरी या वेट-गेट-मोर वैरिएबल का प्रतिमान होता है। इसके अलावा, बारिश में होने वाले बदलाव में वैश्विक औसत वृद्धि का अर्थ है औसत वर्षा में वृद्धि के दोगुने से अधिक तेज होना है।

पहले क्रम में बढ़ी हुई वर्षा में बदलाव, जलवायु के गर्म होने के चलते हवा में जल वाष्प में वृद्धि के कारण होती है। लेकिन आंशि-ाक रूप से कमजोर प्रसार में बदलाव नहीं होता है। उत्तरार्द्ध के बारिश में होने वाले बदलाव क्षेत्रीय पैटर्न पर हावी होते है। यह अध्ययन साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है।

औसत स्थिति और वर्षा में होने वाले बदलाव दोनों में परिवर्तन पर गौर करने से, भविष्य में किए जाने वाले शोधों के लिए वर्षा में होने वाले बदलावों को समझने के लिए एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। झांग वेन्क्सिया ने कहा लगभग दो-तिहाई भूमि अधिक नमी और जलवायु में अधिक बदलाव का सामना करेगी, जबकि शेष भूमि क्षेत्र सूखे के रूप में अधिक बदलावों का सामना करने का अनुमान है। यह अलग-अलग बारिश संबंधी बदलावों की व्यवस्थाओं का मूल्यवान है।

दुनिया भर में बारिश में होने वाले अधिक बदलाव के लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेवार है जो हमारे जलवायु को और अधिक असमान बना रहा है। नमी और सूखी दोनों ही स्थितियों के तेजी से बढ़ने के आसार हैं। अधिक बारिश की अधिक बदलाव वाली घटनाएं आगे चलकर फसल की पैदावार और नदी के प्रवाह पर प्रभाव डाल सकती हैं। यह दोनों बुनियादी ढांचे, मानव समाज और पारिस्थितिकी तंत्र की मौजूदा जलवायु से निपटने को चुनौती देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को और अधिक कठिन बना देता है।

जलवायु परिवर्तन से किस तरह बढ़ रहे हैं मानव-वन्यजीव संघर्ष

मानव-वन्यजीव संघर्षों का व्यापक अध्ययन किया गया है। शोध से पता चलता है कि जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, जीवन की गुणवत्ता और भी बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन संघर्षों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विचार करने के लिए, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ठोस प्रयास से हमें यह अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है कि ये संघर्ष कब होंगे और शायद हम उनसे बच भी सकते हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष जलवायु परिवर्तन संबंधी मामले दर्जनों से भी अधिक हैं। लेकिन ये घटनाएं अलग-अलग हैं, उनकी एक दूसरे से तुलना करना कठिन है। अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियां मानव-वन्यजीव संपर्क के बीच अधिक सीधा संबंध बनाते हैं, जैसे व्हेल का जालों में फंसना। प्रोफेसर अब्राहम ने कहा की कुछ ही अध्ययनों ने जलवायु और मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच संबंध को पहचाना है। जिसमें हाल ही में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की रिपोर्ट भी शामिल है। लेकिन व्यापक वैज्ञानिक समुदाय द्वारा यह प्रत्यक्ष मान्यता नहीं मिली है कि जलवायु परिवर्तन अधिक तीव्र और बार-बार मानव-वन्यजीव संघर्षों को बढ़ावा देने वाला है।

शोधकर्ता का मानना है कि अधिकतर अध्ययनों ने जलवायु की भूमिका पर विचार नहीं किया है। यह इतनी जटिल प्रक्रिया है इसे समझना काफी कठिन है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो संघर्षों को पैदा करते हैं।

छत्तीसगढ़ में बाघ संरक्षण की बढ़ती चुनौती

राज्य के तीनों टाइगर रिजर्व अब माओवादी क्षेत्र में

छत्तीसगढ़ के दो टाइगर रिजर्व पहले से माओवादी क्षेत्र में थे अब तीसरे यानी अचानकमार टाइगर रिजर्व को भी माओवाद प्रभावित जिलों में शामिल कर लिया गया है।

राज्य में बाघ संरक्षण की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। 2014 की गणना में राज्य में 46 बाघ थे, जबकि 2018 की गणना में लगभग 19 बाघों के होने का अनुमान है। और अब तीनों टाइगर रिजर्व के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में आ जाने से संरक्षण की राह अभी और मुश्किल होगी।

जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों की बात मानें तो माओवाद से प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाली टाइगर रिजर्व में संरक्षण काफी मुश्किल है। कैमरा ट्रैप से लेकर बाघों के खाने-पीने के लिए जरूरी जीव-जंतुओं पर नजर रखना सब मुश्किल होता है।

बढ़ते तापमान से लद्दाख की जांस्कर घाटी में पीछे हट रहे हैं ग्लेशियर

दयानिधि

अध्ययन से पता चलता है कि हवा के तापमान में निरंतर वृद्धि के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं

लद्दाख के जांस्कर में स्थित पेन्सिलुंगपा ग्लेशियर (पीजी) पीछे हट रहा है और हाल के एक अध्ययन ने सर्दियों के दौरान तापमान में वृद्धि और वर्षा में कमी को पीछे हटने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 2015 से, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, ग्लेशियोलॉजी, यानी ग्लेशियर के स्वास्थ्य (मास बैलेंस) निगरानी, डायनेमिक्स पर विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है।

पिछली जलवायु की परिस्थितियों, भविष्य के जलवायु परिवर्तन की अटकलें और इस क्षेत्र में ग्लेशियरों पर इसके प्रभाव को लेकर अध्ययन जारी है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने हिमालय के कम खोजे गए क्षेत्र, यानी लद्दाख के जांस्कर का अध्ययन किया है।2016-2019 के बाद से ग्लेशियर की सतह पर स्टेक नेटवर्किंग के माध्यम से इनके बारे में पता लगाया गया हैं। स्टेक नेटवर्किंग - बांस से बना एक खूंटा है जिसे ग्लेशियर की सतह पर गाड़ दिया जाता है, ताकि इसको मापा जा सके। इस तरह ग्लेशियरों से संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया गया है। इसमें ग्लेशियरों के द्रव्यमान संतुलन के लिए क्षेत्र के आधार पर, उन्होंने इसके प्रभाव का आकलन किया। जलवायु परिवर्तन के चलते पेनसिलुंगपा ग्लेशियर (पीजी), हिमालय, लद्दाख के जांस्कर के अतीत और वर्तमान में आए अंतर को दिखाता है। पिछले 4 वर्षों यानी 2015 से 2019 के बीच इस क्षेत्र के अवलोकन से पता चला है कि ग्लेशियर अब 6.7 ± 3 मीटर ए-1 की औसत दर से पीछे हट रहा है। जर्नल रीजनल एनवायर्नमेंटल चेंज में प्रकाशित अध्ययन में, टीम ने पेन्सिलंगपा ग्लेशियर के देखे गए पीछे हटने के रुझान के लिए तापमान में वृद्धि और सर्दियों के दौरान वर्षा में कमी को जिम्मेदार ठहराया।

अध्ययन विशेष रूप से गर्मियों में ग्लेशियर के द्रव्यमान संतुलन और पीछे हटने पर मलबे के आवरण के महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर इशारा करता है। इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों, 2016 से 2019 के बीच के आंकड़ों से पता चलता है कि यह लगातार पीछे हट रहा है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप हवा के तापमान में निरंतर वृद्धि के कारण, ग्लेशियर के पिघलने में वृद्धि होगी। यह भी आसार हैं कि अधिक ऊंचाई पर गर्मी के चलते बारिश बर्फ में न बदलकर पानी में बदल जाएगी और यह गर्मी और सर्दी के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है।

महिला हॉकी टीम की झारखंडी खिलाड़ियों को 50 - 50 लाख मिलेंगें

संवाददाता

रांची : टोक्यो ओलिम्पिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को भले ही कांस्य पदक भी नहीं मिल सका, लेकिन टीम ने कांस्य पदक के मैच में पिछले ओलिम्पिक की स्वर्ण पदक विजेता ग्रेट ब्रिटेन की टीम को जिस प्रकार टक्कर दी, वह काबिले तारीफ है।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक भावुक संदेश में कहा कि ....मैं पूरी भारतीय महिला हॉकी टीम को सलाम करता हूं। झारखण्ड की बेटियों और मेरी बहनों ने भारतीय महिला टीम के प्रदर्शन में अद्भुत योगदान दिया। झारखण्ड सरकार ने ओलिंपिक शुरू होने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि राज्य के खिलाड़ियों के स्वर्ण जीतने पर दो करोड़, रजत जीतने पर एक करोड़ और कांस्य जीतने पर पचास लाख रुपये दिये जायेंगे। भारतीय महिला टीम कांस्य की जंग में जीत नहीं पाई। झारखण्ड की बेटियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल सभी झारखण्ड की बेटी खिलाड़ियों को सरकार अपने पूर्व के फैसले को संशोधित कर 50-50 लाख रुपये देगी और सभी के पैतृक घर को पक्के के मकान में तब्दील करायेगी । भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंच कर इतिहास रच दिया और अपने जज्बे से साबित कर दिया कि वह दुनिया की बेहतर से बेहतर टीम को टक्कर देने का माद्दा रखती है। भारतीय महिला टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने में हर एक खिलाड़ी, कोच और सभी सपोर्ट स्टाफ का अतुलनीय योगदान है सभी के प्रति मैं और पूरा झारखण्ड दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई और भविष्य के लिये शुभकामनाएं देता है। झारखण्ड सरकार खेल के क्षेत्र में आगे आने वाले खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के प्रति दृढसंकल्पित है। अभी हाल में ही हमारी सरकार ने खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान की है। यह क्रम जारी रहेगा। हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारी सरकार उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करेगी ताकि दुनिया भर में भारत का डंका बजे और झारखंडी खिलाड़ियों का लोहा हर कोई माने।

खतरनाक केकिकल्स के संपर्क में आने से हर रोज मरते हैं 5,480 लोग

जहां 2016 में खतरनाक केमिकल्स के कारण 15.6 लाख लोगों की जान गई थी, वहीं 2019 में इससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 लाख पर पहुंच गया था

किरण पांडेय /ललित मौर्य

दुनिया भर में खतरनाक केमिकल्स जैसे लीड, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एस्बेस्टस, बेंजीन के संपर्क में आने से हर साल करीब 20 लाख लोग मारे जाते हैं। यदि दैनिक आधार पर देखें तो यह आंकड़ा करीब 5,480 मौतें प्रतिदिन बैठता है। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों को देखें तो 2016 से 2019 के बीच इन हानिकारक केमिकल्स से होने वाली मौतों में 28.2 फीसदी की वृद्धि हुई है।

जहां 2016 में इसकी वजह से 15.6 लाख लोगों की जान गई थी वहीं 2019 में इससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 लाख पर पहुंच गया था। वहीं यदि अकेले लेड के बात करें तो इससे होने वाली मौतों में करीब 67 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। जिसका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और वयस्क बनते हैं। यदि स्वास्थ्य से जुड़े सतत विकास के लक्ष्यों को देखें तो उनका मकसद दुनिया को इन खतरनाक रसायनों से बचाना है। साथ ही इनकी वजह से होने वाले वायु, जल और मृदा प्रदूषण को कम करना और उससे होने वाली बीमारियों को रोकना है। ऐसे में यह नए अनुमान एक बार फिर इन केमिकल्स के नियमन और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता को दोहराते हैं।

भारत को भी इस पर ध्यान देना चाहिए क्यों देश की नेशनल केमिकल पालिसी 2012 से लंबित है। सीपीसीबी के पूर्व वैज्ञानिक डीडी बासु ने भी केमिकल्स के उपयोग, उत्पादन और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए देश में व्यापक कानून की आवश्यकता की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हानिकारक केमिकल्स हवा, मिट्टी, पानी, कार्यस्थल और उपभोक्ता उत्पादों में भी मौजूद रहते हैं जो कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जिनसे मानसिक और व्यवहारिक विकार, मोतियाबिंद, अस्थमा, कैंसर और तंत्रिका सम्बन्धी विकार हो सकते हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इनसे होने वाली अधिकांश मौतों को टाला जा सकता है। इसके लिए इन रसायनों के उपयोग को बंद कर देना या इनके जोखिम को कम करने से जुड़े उपायों को अपनाया जा सकता है।

करीब 45 फीसदी मौतों के लिए अकेले लेड है जिम्मेवार

दुनिया भर में हानिकारक केमिकल्स से होने वाली कुल मौतों में से करीब 45 फीसदी मौतों के लिए अकेले लेड जिम्मेवार है। वहीं 2016 से 2019 के बीच इसके कारण होने वाली मौतों में करीब 67 फीसदी का इजाफा हुआ है। लेड या सीसे के सम्पर्क में आने से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां (सीवीडी), क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) और आईआई डी जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं। 2019 में इसके संपर्क में आने से करीब 9 लाख लोगों की जान गई थी। जिसमें से हर 10 में से नौ लोगों की मौत कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण हुई थी। यदि देखा जाए तो रंग की मात्रा को बढ़ाने, जंग को कम करने और जल्द सुखाने के लिए पेंट में लेड मिलाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है।

गौरतलब है कि 2020 में यूनिसेफ ने भी बच्चों के स्वास्थ्य पर लेड प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई थी। इस पर यूनिसेफ ने जारी अपनी रिपोर्ट 'द टॉक्सिक ट्रुथ' में कहा था कि दुनिया के हर तीसरे बच्चे के रक्त में लेड की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा है।

अनुमान है कि दुनिया के करीब 80 करोड़ बच्चों में लेड की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा है। हालांकि इस-के बावजूद दुनिया में अभी भी बिना रोकटोक के लेड का उपयोग जारी है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत सहित केवल 41 फीसदी देशों ने लेड युक्त पेंट के उत्पादन, आयात, बिक्री और उपयोग से जुड़े नियम बनाए हैं वहीं अभी भी अफ्रीका के 17 देशों में इससे जुड़े कोई नियम क़ानूनी रूप से लागू नहीं किए गए हैं। वहां आज भी इनका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसके साथ ही इन केमिकल्स से होने वाली मौतों के लिए क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) से लेकर पार्टिकुलेट और कैंसर जैसी बीमारियां जिम्मेवार हैं जो कार्यस्थल पर हानिकारक केमिकल्स के संपर्क में आने से होती हैं। अनुमान है कि कार्यस्थल पर धूल, धुएं और गैस के संपर्क में आने से सीओपीडी के कारण हर साल करीब 5 लाख लोगों की जान जाती है वहीं आर्सेनिक, एस्बेस्टस, बेंजीन जैसे केमिकल्स के कारण होने वाले कैंसर से हर साल 35 लाख से अधिक लोगों की असमय मौत हो जाती है।

हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से 2019 में जो विकलांगता हुई हैं उनके कारण कुल 5.3 करोड़ वर्षों का नुकसान हुआ है। 2016 में यह आंकड़ा करीब 4.5 करोड़ वर्ष था, जिसका मतलब है कि इन वर्षों के दौरान इसमें करीब 19 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं यदि लेड की बात करें तो इसके संपर्क में आने से 2016 की तुलना में विकलांगता-समायोजित जीवन-वर्षों में लगभग 56 फीसदी की वृद्धि हुई है डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार 2019 में इसके कारण हुई विकलांगता के कारण 2.16 करोड़ स्वस्थ जीवन वर्षों का नुकसान है था। ये चिंताजनक आंकड़ें डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक द्वारा 7 जुलाई 2021 को 'बर्लिन फोरम ऑन केमिकल्स एंड सस्टेनेबिलिटी: एम्बिशन एंड एक्शन टु 2030' में आयोजित मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान जारी किए गए थे।

प्रधान वित्त सलाहकार सह अध्यक्ष दक्षिण पूर्व रेलवे खेल संघ ने किया रांची दौरा

संवाददाता, रांची : 06-अगस्त को मुख्यालय गार्डन रीच, कोलकाता, से प्रधान वित्त सलाहकार सह अध्यक्ष दक्षिण पूर्व रेलवे खेल संघ प्रशांत कुमार मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर रांची आए , तथा हटिया स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्टेडियम पर उपलब्ध खेल सुविधा एवं अन्य सुविधाओं को देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया, तथा भविष्य की परियोजनाओं की जानकारी ली एवं उनका गहन निरीक्षण भी किया।

इस दौरान उन्होंने हॉकी की पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमती सुमराए टेटे, श्रीमती असुंता लाकड़ा, श्रीमती सावित्री पूर्ति, श्रीमती सुभद्रा प्रधान, श्रीमती राजकुमारी बांद्रा एवं क्रिकेटर श्री कुलदीप शर्मा से मिलें तथा हॉकी स्टेडियम के विस्तार को लेकर चर्चा की।

हॉकी स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) श्री एम एम पंडित, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मंडल कीड़ा अधिकारी अवनीश, मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह संयुक्त क्रीडा अधिकारी डॉ देवराज बनर्जी, सहायक यांत्रिक अभियंता सह सहायक क्रीड़ा अधिकारी अरुण कुमार सिंह खेल सचिव प्रशांत मुखर्जी एवं अन्य कर्मचारी तथा खिलाड़ी उपस्थित थे।

सीसीएल : अधिकारियों के आश्रितों के इंस्योरेंस रकम बैंक में ट्रांसफर

संवाददाता: सीसीएल ऑफिसर्स बेनिवोलेन्ट सोसाईटी (ओबीएस)द्वारा कोरोना के कारण निधन हो गये अपने 3 अधिकारियों के आश्रितों को ग्रुप इंस्योरेंसका रकम चेक तथा बैंक में फंड ट्रांसफर के द्वारा दिया गया। इनमें से (1) श्रीमती मिनाल सिद्धार्थ धर्मपत्नी स्व. संजीव प्रसाद, उप प्रबंधक (वित्त) मुख्यालय को 5,44,206 रू. का चेक श्री राजेन्द्र सिंह, महाप्रबंधक (एफ.पी.सी.) ने प्रदान किया और (2) श्रीमती रेणु सिंह धर्मपत्नी स्व. विजय शंकर सिंह, मुख्य प्रबंधक (एमएम), मुख्यालय को 5,44,808 रू. का तथा (3) श्रीमती प्रनति मंडल धर्मपत्नी स्व. अमलेन्दु मंडल, मुख्य प्रबंधक (उत्खनन), ईसीएल को 5,73,556 रू. का ग्रुप इंस्योरेंस का रकमउनकेबैंक खाता में फंड ट्रांसफर के माध्यम से किया गया।

इस अवसर पर सीसीएल ओबीएस के महासचिव राजकुमार सिंह, उपाध्यक्ष आर. आर. शर्मा, कोषाध्यक्ष श्रीमती कुमारी प्रतिभा, विनय कुमार शंकर, सुरेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारीगण सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे।

गरीब मजदूर, किसान, ऑटो ड्राइवर के बच्चों ने भी अपना परचम लहराया

संवाददाता

सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 'सीसीएल के लाल' एवं 'सीसीएल की लाडली' का शानदार प्रदर्शन

रांची :सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) की महत्वाकांक्षी योजना'सीसीएल के लाल'एवं 'सीसीएल की लाडली'के बच्चों ने 2021 की सीबीएसई की 12वी की परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन रहा। यहाँ के बच्चों ने 97% तक अंक लाकरअपने परिवार तथा कंपनी की गरीमा बढ़ाई है। 27 विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थियों ने 95 से अधिक अंक अर्जित कर अपना परचम लहराया है। विदित हो किरिद्धी कुमारी (96.2%)केपिता छोटन प्रसाद एक किसान हैं, जया रानी (91.2%)केपिता श्री सुरेश सावएक ऑटो ड्राईवर, रौशन सिंह (97.2%)के पिता संतोष सिंह एक प्राईवेट कर्मचारी, अनुज कुमार (91.6%)के पिता उपेन्द्र विश्वकर्मा सीएमडी सीसीएल पी एम प्रसाद, निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, निदेशक (कार्मिक) पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुना राव, निदेशक (वित्त) के.आर. वासुदेवनएवं महाप्रबंधक सीएसआर ने सभी बच्चों की इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना किया है। उन्होंने लाल लाडली के प्रशिक्षकों सहित सीएसआर की पूरी टीम को भी बधाईयां दी और उनके इस नेक काम की सराहना भी की।

सीसीएल के लाल द्वारा प्राप्त अंक (%में): रोशन सिंह - 97.2, करन राज -96.6, रोशन कुमार -96.6 कुमार आयुष - 96.6 आदित्य सिंह - 95.6 शम्स आरीज -95.4 आशु कुमार - 95.2 मो. साहिल अमन - 94.8 अनुज कुमार - 94 आयुश आनंद - 93.2, अनुज कुमार - 91.6, अमन कुमार - 90.4, अनुराग दास - 88.6, अमन कुमार गुप्ता - 87.8 सीसीएल की लाडली द्वारा प्राप्त अंक (%में):तोषी मेहता - 96.6, ऋद्धि कुमारी - 96.2, अदिति सिंह - 96, खुशबू कुमारी -95.8, आकृति आदर्श - 95.6, तेजस्वी कुमारी - 95.4, सपना रानी - 93.8, आशी रानी - 93.4, तिथि 92.8, जया रानी 91.2, मुस्कान गुप्ता 90.6, श्रुति कुमारी 90.4, सपना कुमारी 87

सीसीएल के लाल इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 'सीसीएल के लाल'एवं ' सीसीएल की लाडली'के बच्चों को निःशुल्क आईआईटी करायी जाती है। सीसीएल के अधिकारीगण जो स्वंय आईआईटी के छात्र रहे हैं वे स्वतः सीसीएल के लाल एवं सीसीएल की लाडली का प्रशिक्षण शिक्षक के रूप में योगदान दे रहें हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रतिभावान छात्र जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और उन्हें सीसीएल द्वारा डीएवी स्कूल गांधीनगर, रांची में दाखिला कर निःशुल्क शिक्षण, आवास एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। सीसीएल के लाल एवं सीसीएल की लाडली के बच्चों का चयन 10वीं कक्षा के बाद किया जाता है। सभी छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा के साथ-साथ आईआईटी - जेईई का भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

भारत वैश्विक मीथेन पहल (जीएमआई) की संचालन समिति का उपाध्यक्ष बना

संवाददाता

भारत अब वर्ष 2021-2023 के लिए ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव (टेक) की संचालन समिति का उपाध्यक्ष बना। भारत जीएमआई के 45 भागीदार देशों में संस्थापक सदस्य है। अब भारत आने वाले वर्षों में मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। विनोद कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत के उपाध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिच्यूट (सीएमपीडीआई) संचालन समिति के सदस्य और कोयला उपसमिति के सह-अध्यक्ष होंगे। एचओडी स्वच्छ ऊर्जा विभाग, सीएमपीड-ीआई वैकल्पिक प्रतिनिधि होंगे। कनाडा संचालन समिति का अध्यक्ष है और अमेरिका के समिति के अन्य उपाध्यक्ष होने की संभावना है।

जीएमआई एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मीथेन की वसूली और उपयोग के लिए बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है। यह पहल दुनिया भर में मीथेन-से-ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ सूचना संसाधनों को अपने व्यापक ऑनलाइन पुस्तकालय के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकी उपकरणों और संसाधनों के माध्यम से तैनात करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए, जीएमआई तीन प्रमुख क्षेत्रों: तेल और गैस, बायोगैस और कोयला खानों में मीथेन शमन को आगे बढ़ाने के लिए सूचना और तकनीकी संसाधनों का आदान-प्रदान करने के लिए अपने सहयोगी देशों और 700 से अधिक प्रोजेक्ट नेटवर्क सदस्यों के साथ सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त, जीएमआई जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग , और ऊर्जा एजेंसी (आईईए) सहित मीथेन वसूली और उपयोग पर केंद्रित अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करता है।

सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के लीजहोल्ड क्षेत्रों में सीबीएम और सीएमएम के विकास के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। हाल ही में सीबीएम डेवलपर के माध्यम से विकसित करने के लिए तीन सीबीएम ब्लॉकों की नीलामी की गई है। बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्रों में झरिया सीबीएम ब्लॉक के विकास के लिए सीबीएम डेवलपर का चयन किया गया है। मूनीडीह भूमिगत खदान के लिए कोल माइन मीथेन ड्रेनेज प्रदर्शन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

आदिवासियों ने परंपरा,मानवता और संस्कारों को सहेजा है

संध्या

पुरे विश्व में आदिवासी जनजाति को बढ़ावा देने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए पुरे विश्व में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यानी मनाया जाता हैं। इस दिवस को मनाने के लिए सबसे पहली बार शुरुआत सयुंक्त राज्य अमेरिका में 1994 में किया गया था। आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हैं "आदि" और "वासी" जिसका अर्थ होता हैं निवासी।

पूरे विश्व में अगर संस्कारों, परंपराओं और प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाये तारतम्य बना कर रहने की कला को जीवित रखा है तो वह आदिवासी ही हैं। पर्व त्यौहारों से लेकर शादी विवाह गीत संगीत के रीती रिवाजों को आदिवासी समाज ने ही अक्षुण्ण रखा है।

भारत में तक़रीबन 8 प्रतिशत जनसँख्या आदिवासी हैं। 8 प्रतिशत यानी करीब 10 करोड़। भारतीय संविधान में आदिवासी जाति के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द इस्तेमाल किया गया। भारत की आदिवासी जातियों में जाट, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बोडो, भील, खासी, सहरिया, संथाल, मीणा, उरांव, परधान, बिरहोर, पारधी, आंध,टोकरे कोली, महादेव कोली,मल्हार कोली, टाकणकार आदि जातिया शामिल हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में मूल रूप में लेपचा, भूटिया, थारू, बुक्सा, जॉन सारी, खाम्पटी, कनोटा जातियां प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, मिजोरम, नगालैंड, मेघालय आदि) में लेपचा, भारी, मिसमी, डफला, हमर, कोड़ा, वुकी, लुसाई, चकमा, लखेर, कुकी, पोई, मोनपास, शेरदुक पेस प्रमुख हैं। पूर्वी क्षेत्र (उड़ीसा, झा-रखंड, संथाल, बंगाल) में जुआंग, खोड़, भूमिज, खरिया, मुंडा, संथाल, बिरहोर हो, कोड़ा, उंराव आदि जातियां प्रमुख हैं। इसमें संथाल सबसे बड़ी जाति है। पश्चिमी भारत (गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र) में भील, कोली, मीना, टाकणकार, पारधी, कोरकू, पावरा, खासी, सहरिया, आंध, टोकरे कोली, महादेव कोली, मल्हार कोली, टाकणकार आदि प्रमुख है। अंग्रेजी का नेटिव शब्द मूल निवासियों के लिये प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी के ट्राइबल शब्द का अर्थ 'मूलनिवासी' नहीं होता है। ट्राइबल का अर्थ होता है 'जनजातीय'। विकासक्रम के चलते पहले ग्राम बने फिर कस्बे और अंत में नगर। यहीं से विभाजन होना प्रारंभ हुआ। जो वन में रह गए वे वनावासी, जो गांव में रह गए वे ग्रामवासी और जो नगर में चले गए वे नगरवासी कहलाने लगे। 400 पीढ़ियों के प्रारंभिक काल में ये जातियां थीं- देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्ल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्ध, मरुदगण, किन्नर, चारण, भाट, किरात, रीछ, नाग, विद्याधर, दार्द, पक्थ (पख्तून), अहीर, मेघ, मानव , वानर, निषाद, मत्स, अश्मक, कलिंग, यवन, शिना, शूर, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रुह्मु, अलिन, भलान, शिव, विषाणिन, कक्कड़, खोखर, चिन्धा चिन्धड़, समेरा, कोकन, जांगल, शक, पुण्ड्र, ओड्र, मालव, क्षुद्रक, योधेय जोहिया, तक्षक व लोहड़, मद्र, कंबोज, भरत, आदि। कालक्रम के चलते इने नाम बदलते गए। भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गोरे, काले, सांवले, लाल और गेहूंवे रंग के हैं। एक ही परिवार में कोई काला है तो कोई गोरा, एक ही समाज में कोई काला है तो कोई गोरा। सभी वर्गों में सभी तरह के रंग के लोग आपको मिल जाएंगे। कश्मीरी ब्राह्मण गोरे हैं तो दक्षिणी ब्राह्मण काले। दक्षिण भारत में अधिकर लोग काले रंग के होते हैं। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और हिन्दुओं में दलित और ब्राह्मण सभी काले रंग के हैं। इस तरह हम भारतीयों के नाक-नक्ष की बात करें तो वह चीन और अफ्रीका के लोगों से बिल्कुल भिन्न है।

आर्यों को कोई सेंट्रल एशिया कहता है, तो कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया, तो कोई ट्रांस कोकेशिया, तो कुछ ने आर्यों को स्कैंडेनेविया का बताया। परंतु यह आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आई खोज के अनुसार आर्य आक्रमण नाम की चीज न तो भारतीय इतिहास के किसी कालखण्ड में घटित हुई और ना ही आर्य तथा द्रविड़ नामक दो पृथक मानव नस्लों का अस्तित्व ही कभी धरती पर रहा। वेदों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आर्यों, दासों, दस्युओं में नस्लीय भेद को प्रदर्शित करता हो।

भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी है लेकिन चूंकि विकासक्रम में भारतीय वनों में रहने वाले आदिवासियों ने अपनी शुद्धता बनाए रखी और वे जंगलों के वातावरण में खुले में ही रहते आए हैं तो उनकी शारीरिक संवरचना, रंग-रूप, परंपरा और रीति रिवाज में को खास बदलावा नहीं हुआ। हालांकि जो आदिवासी अब गांव, कस्बे और शहररों के घरों में रहने लगे हैं उनमें धीरे धीरे बदलाव जरूर आएंगे। प्रारंभिक मानव पहले एक ही स्थान पर रहता था। वहीं से वह संपूर्ण विश्व में समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बसता गया। विश्वभर की जनतातियों के नाक-नक्ष आदि में समानता इसीलिए पायी जाती है क्योंकि उन्होंने निष्क्रमण के बाद भी अपनी जातिगत शुद्धता को बरकरार रखा और जिन आदिवासी या जनतातियों के लोगों ने अपनी भूमि और जंगल को छोड़कर अन्य जगह पर निष्क्रमण करते हुए इस शुद्धता को छोड़कर संबंध बनाए उनमें बदलाव आता गया। यह बदलाव वातावरण और जीवन जीने के संघर्ष से भी आया।

छात्रा: पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग रांची विवि, रांची

जग से प्यारी है प्रकृति हमारी

प्रिया सिंह

जहां सुबह शाम होती है लाली
जिनके चारो ओर हरियाली
रूप है बहारों वाली, जग से प्यारी है प्रकृति हमारी।
हरे भरे इसके वन और उपवन, जहां हैं ऊंचे पर्वत,
बहती झील और नदियां
मन को मोहित करने वाली है यह दुनिया
प्रकृति फल, फूल जल , हवा देने वाली
ऐसे जैसे मां सी सेवा करने वाली
जिसके चारो ओर है हरियाली
जग से प्यारी है प्रकृति हमारी।
हर क्षण को बदल कर मन बहलाने वाली
कहीं सूखा, कहीं बाढ, कभी सुनामी तो कभी भूकंप लाकर
अपनी नाराजगी जताने वाली
रोक दो लोगों प्रदूषण को वर्ना
कहीं सो न जाये प्रकृति हमारी
जहां सुबह शाम होती है लाली
जग से प्याारी प्रकृति हमारी।

क्या सदैव गरीब फटेहाल ही रहेगा हमारा किसान ?

निशा नायक

भारत में 1000 से तक पौधे उगाने फसलें उगाने तथा पशु पालने और कृषि करने का काम शुरू हो गया था शीघ्र ही यहां के मानव ने व्यवस्थित जीवन जीना शुरु किया और कृषि के लिए औजार तथा तकनीकें विकसित कर ली मानसून होने के कारण एक ही वर्ष में दो फसलें ली जाने लगी इसके फलस्वरूप भारत कृषि उत्पाद तत्कालीन वाणिज्य के द्वारा विश्व बाजार में पहुंचाना शुरू हो गया दूसरे देशों से भी कुछ फसलें भारत में आई एवं पशु की पूजा भी की जाने लगी जीवन के लिए उनका महत्व समझना शुरू हो गया ।

कृषि का विकास कम से कम 1000 -13000 वर्ष पूर्व हो चुका था तब से अब तक बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं कृषि भूमि को खोदकर अथवा जोड़कर और बीज बोकर व्यवस्थित रूप से अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृषि अथवा खेती कहते हैं। उसने पहले पहल कब कहां और कैसे खेती करना आरंभ किया,देशों के इतिहास में खेती के विषय में कुछ ना कुछ कहा गया है कुछ भूमि अब भी ऐसी है जहां पर खेती नहीं होती अफ्रीका और अरब के रेगिस्तान, तिब्बत एवं मंगोलिया के ऊंचे पठार तथा मध्य ऑस्ट्रेलिया कांगो के बौने और अंडमान के बनवासी खेती नहीं करते।

कृषि से किसानों के जीवनयापन पर गौर करें तो ,प्राचीन काल से अब तक का पेट भरने वाला किसान का पेट भूखा है। हमारे कथा कहानियों में भी किसान एक गरीब ,फटेहाल चरित्र ही होता है । आज के संदर्भ में देखें तो आजादी से अब तक किसानों का आय और व्यक्ति की तुलना में 50% की वृद्धि नहीं हुआ है। रोजगार करने वाले या सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं वही किसान के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं किसानों का पहनावा रहन-सहन निम्न है। अन्य लोगों का बैंक बैलेंस जहां लाखों करोड़ों में है वही किसान आज भी ऋण और कर्ज में डूबा है। हमें इन बातों पर गंभीर चिंतन मंथन की जरूरत है कि आज कृषि विकास अनुसंधान किसान कल्याण के कई मंत्रालय और विभाग हैं जिन पर सरकार अरबों खर्च करती है परंतु कृषि और किसानों का जो उन्नति और विकास होना चाहिए था वह आज तक नहीं हो पाया। हर रोज दस हजार लोग आज देश में कृषि छोड़ रहे हैं, तो क्या एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि देश में कोई किसान ही नहीं होगा और ना इस उद्यम को कोई अपनाना चाहेगा? या फिर सरकार और सरकारी योजनाएं ऐसी आयें जिससे कृषि के दिन बहुर जायें, किसानों का भी एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, किसानों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे , इनका जीवन स्तर भी औरों की तरह उच्च हो जायेगा?

छात्रा: पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, रांची विवि, रांची

जंगलों में आग लगने की घटनाएं 350 प्रतिशत बढ़ीं ओडिशा और मध्य प्रदेश में 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी

भगीरथ श्रीवास

नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच देशभर में आग लगने की करीब 3.5 लाख चेतावनियां दी गईं

देशभर में जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव जनित कारणों से वनों में आग लगने की घटनाएं तीन गुना से अधिक बढ़ गई हैं। इस संबंध में लोकसभा में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 30 जुलाई को बताया कि देशभर में आग लगने की घटनाओं की संख्या वर्ष दर वर्ष बदलती रही है। उन्होंने बताया कि वनों में लगने वाली अधिकांश आग जमीनी होती है जिनमें वनस्पतियां आदि जल जाती हैं।

लोकसभा में उपलब्ध कराए आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2019 से जून 2020 के बीच आग लगने की कुल 1,24,473 घटनाएं हुई थीं जो नवंबर 2020 से जून 2021 को बढ़कर 3,45,989 हो गईं। यानी आग लगने की घटनाओं में 350 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2018 से जून 2020 के बीच ऐसी 2,10,286 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

ओडिशा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लगी आग

केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दावानल की घटनाओं में इजाफा हुआ है। नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच आग लगने की सबसे अधिक 51,968 घटनाएं ओडिशा में दर्ज की गईं। राज्य में नंवबर 2019 से जून 2020 के बीच दावानल की कुल 10,602 घटनाएं दर्ज की गई थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक वर्ष में ओडिशा में आग लगने की घटनाएं करीब 500 प्रतिशत बढ़ गईं। ओडिशा के बाद दावानल की सबसे अधिक घटनाएं मध्य प्रदेश में हुईं। यहां नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच ऐसी कुल 47,795 घटनाएं हुईं जो नंवबर 2019 से जून 2020 के बीच की 9,537 घटनाओं से करीब 500 प्रतिशत अधिक हैं। महाराष्ट्र में नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच 34,025 घटनाएं, छत्तीसगढ़ में 38,106 घटनाएं, उत्तराखंड में 21,487 घटनाएं, झारखंड में 21,712 घटनाएं दर्ज की गईं। ये आंकड़े पिछले वर्ष से कई गुना अधिक हैं।

कुछ राज्यों में कम लगी आग

राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आग लगने की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।

राजस्थान में नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच 3,402 घटनाएं सामने आईं जो पिछले वर्ष की 3,461 घटनाओं से थोड़ा कम है। इसी तरह केरल में 296 घटनाएं दर्ज की गईं जो पिछले वर्ष की 864 घटनाओं से काफी कम हैं। चंडीगढ़ में आग लगने की कोई भी घटना दर्ज नहीं की गई।

बाढ़ और भारी बारिश से 65 साल में 1 लाख लोगों की मौत, 4 लाख करोड़ का नुकसान

एजेंसियां:भारत का लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। देश में 1953 से लेकर 2018 के दौरान बाढ़ और भारी बारिश के कारण 1,09,374 लोगों की जान गई, जबकि 61,09,628 पशुओं की जान गई। अनुमान है कि इन 65 सालों के दौरान देश को लगभग 4,00,097 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

17वीं लोकसभा के लिए संसद की स्थायी समिति (जल संसाधन) द्वारा दोनों सदनों में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का यह आंकड़ा बहुत प्रचंड है। हर साल बाढ़ से होने वाले भारी नुकसान के लिए खराब योजना, बाढ़ नियंत्रण नीतियों की असफलता, अधूरी तैयारियां और निष्प्रभावी आपदा प्रबंधन जिम्मेवार है। स्थायी समिति ने कहा कि जिस तरह से हर साल बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब समय आ गया है, जब केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में काम करें। समिति ने एक इंटिग्रेटेड रिवर बेसन मैनेजमेंट प्लान बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों के साथ-साथ पड़ोसी देशों को शामिल किया जाए, ताकि पड़ोसी देशों की नदियों के पानी का भी प्रबंधन किया जा सके।स्थायी समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश के पैटर्न में काफी बदलाव आया है। जहां बारिश के कुल दिनों में कमी आई है, वहीं एक साथ भारी बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं। इसलिए अब बहुत जरूरी हो गया है कि योजनाकार बाढ़ नियंत्रण की रणनीति पर नए सिरे से काम करें।

भारतीयों की सेहत बिगाड़ रहा है देर रात तक जगना

कृष्ण कांत ठाकुर

पिछले दो दशकों में भारतीयों में देर रात तक जगकर कंप्यूटरों पर काम करने, सोशल मीडिया औरस्मार्टफोन पर लगे रहने या पार्टी करने गप्पे लड़ाने की आदत बढी है। वहीं काम के बोझ में रात्रि विश्राम के बजाय काम के बोझ में दबे रहना भी एक समस्या बन कर उभरी है। इसके कारण ही अवसाद से लेकर, अनिद्रा, तनाव व अन्य बीमारियां भारतीयों की सेहत बिगाड़ रही हैं। वहीं इससे उपजी डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है जो एक बार चपेट में लेती है तो इसका पता लगाना भी आसान नही होता और वहीं अगर नींद पूरी ना हो या फिर देर रात जागा जाए और देर से सोकर उठें तो अवसाद घेर लेता है। इसलिए अगर समय पर सोकर और सुबह जल्दी उठा जाएं तो अवसाद से बचा जा सकता है। सुबह सुर्योदय से पहले यानी 4 से 5 बजे उठने से सबसे ज्यादा फायदा होता है।

पुरानी कहावत :जल्दी सोयें जल्दी जागें

सुबह जल्दी उठने की सभी सलाह देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं खुद विज्ञान भी मानता है कि सुबह जल्दी उठने से कई सारी बीमारियां पास नहीं भटकती। सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोने की आदत कई सारी बीमारियों से आपको बचा लेती है इसमें मानसिक अवसाद एक है। सुबह जल्दी उठने के और फायदे भी हैं।सुबह जल्दी उठने से साफ और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलती है जिससे सांस की समस्याओं से आराम मिलता है और फेफड़ें स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ फेफड़ा कई तरह की बीमारियों से बचाता है।

सुबह तड़के उठकर एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे दिल दुरुस्त रहता है और दिल से जुड़ी बीमारियां पास नहीं भटकती। वहीं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से शरीर चुस्त रहता है और बाकी अंग भी सक्रिय रूप से काम करते हैं। इससे कई मानसिक बीमारिया भी दूर होती है। सुबह उठकर योग या प्राणायाम करने के कई फायदे हैं। वहीं सुबह जल्दी उठकर कसरत करने से दिन भर ताजगी बनी रहती है जिससे काम करने में मन लगा रहता है और सबकुछ समय पर हो जाता है। काम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो खुशी भी साथ आती है।

एक उम्र के बाद हड्डियां अपनी मजबूती खोने लगती हैं। ऐसे में सही खानपान और सही रुटीन और कसरत इन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। रोज सुबह तड़के उठकर कसरत करने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं।

तीसरा सबसे गर्म महीना रहा जुलाई 2021

जून 2021 भी 142 सालों में पांचवां सबसे अधिक गर्म महीना रहा था।

जलवायु संबंधी घटनाओं का रिकॉर्ड टूटना लगातार जारी है। दुनिया भर में जुलाई 2021 तीसरा सबसे गर्म महीना रहा। यूरोपीय संघ के कोपरनिकस अर्थ ऑजर्बेशन प्रोग्राम ने कहा कि जुलाई 2016 और जुलाई 2019 की तुलना में यह मात्र 0.1 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहा।

जुलाई आमतौर पर विश्व स्तर पर वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है, हालांकि अगस्त भी कभी-कभी गर्म हो सकता है। कोपरनिकस ने कहा, अगर 2016 और 2019 के जुलाई माह को छोड़ दें तो जुलाई 2021 का महीना पिछले सभी सालों के महीनों के मुकाबले सबसे गर्म रहा। यहां यह उल्लेखनीय है कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) जलवायु परिवर्तन के विज्ञान पर अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट 9 अगस्त को जारी करेगा। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करेगी। इससे पहले आईपीसीसी ने 2013 में रिपोर्ट जारी की थी।

पिछले महीने भी रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया था। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) की ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जून 2021 के अनुसार, जून के लिए सतह का तापमान 142 वर्षों में पांचवां सबसे अधिक था। यह 20वीं सदी के औसत से 0.88 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि एक रिकॉर्ड है। जुलाई 2021 में वही तापमान दर्ज किया गया, जो पिछले साल इसी महीने में था। यह जुलाई 1991-2020 के महीने के औसत तापमान से 0.33 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था।

यूरोप जो कि हीटवेव और भीषण बाढ़ दोनों की चपेट में है, वहां जुलाई 2021 का औसत तापमान 1991-2020 के औसत से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। कोपरनिकस द्वारा किए गए विश्लेषण में बताया गया है कि केवल जुलाई का रिकॉर्ड जो यूरोप की तुलना में अधिक गर्म था, जबकि यूरोप में 2010 में इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया था। उस समय पश्चिमी रूस में भीषण गर्मी महसूस की गई थी और यूरोप का औसत तापमान 1991-2020 के स्तर से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। पिछले एक वर्ष में, अगस्त 2020 से जुलाई 2021 तक दुनिया भर का सतही तापमान औसत से ऊपर रहा। यह अधिकांश समुद्र की सतह के तापमान के औसत से ऊपर बना हुआ है। यहां बताते चलें कि ठंडे क्षेत्र भी औसत से अधिक गर्म रह रहे हैं।

यूरोपीय संघ के मौसम निकाय ने कहा कि पिछले 12 महीनों में तापमान औसत बना हुआ है, जो उत्तरी साइबेरिया और आस-पास के आर्कटिक समुद्रों, उत्तर पूर्वी कनाडा, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका, मध्य पूर्व और तिब्बती पठार पर तापमान 1991-2020 के औसत से अधिक है।

साभार : डीटीई

भारतीय वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन उत्पादन को तीन गुना बढ़ाने की तकनीक खोजी

इस तकनीक में 10 मिनट के लिए चुंबकीय क्षेत्र का एक बार संपर्क कराने से 45 मिनट से अधिक समय तक उच्च दर के साथ हाइड्रोजन उत्पादन किया जा सकती है

एजेंसियां : भारतीय शोधकर्ताओं ने पानी से हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन को तीन गुना बढ़ाने की तकनीक खोजी है। इस तरह के ऊर्जा उत्पादन में लागत कम लगने के साथ-साथ यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह तकनीक भविष्य में हाइड्रोजन ईंधन की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकती है। एक ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन एक स्वच्छ और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोयले और गैसोलीन जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा स्रोतों की तुलना में यह लगभग 3 गुना अधिक अच्छा है। ऊर्जा पैदा करने के लिए हाइड्रोजन के दहन से पानी पैदा होता है और इस प्रकार यह पूरी तरह से प्रदूषण विहीन है।

प्रो. सी. सुब्रमण्यम की अगुवाई में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस कारनामे को किया है। इसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पानी की इलेक्ट्रोलिसिस शामिल है। यह विधि उसी प्रणाली की तरह है जो 1 मिली हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती है, जबकि नया तरीका उसी समय में 3 मिली हाइड्रोजन का उत्पादन करता है साथ ही इसके लिए 19 फीसदी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रो. सुब्रमण्यम कहते हैं कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का रुक-रुक कर होने वाले ऊर्जा के उपयोग से हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए एक नई दिशा प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए अन्य उत्प्रेरकों की भी खोज की जा सकती है। यह सब देखने के बाद कि यह विधि कठिन नहीं है, टीम अब टीआरएल स्तर को बढ़ाने और इसके सफल व्यवसायीकरण को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। प्रो. सुब्रमण्यम कहते हैं हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था के महत्व को देखते हुए, हमारा लक्ष्य परियोजना को मिशन-मोड में लागू करना है और स्वदेशी मैग्नेटो-इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन जनरेटर का उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि यदि प्रयास सफल होते हैं, तो हम भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, डीजल और कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की जगह ले सकते हैं।

EZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

साइकिल चलाना: एक खेल नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है

अभिजीत कश्यप

"मैं साइकिल चलाने के आनंद की तुलना किसी और चीज से नहीं कर सकता"
जॉन एफ कैनेडी

हॉलैंड के राष्ट्रपति अपने कार्यालय साइकिल से आते जाते थे और तब मीडिया में इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। फिल्म पीके में नायिका पर्दे पर पहली बार साइकिल साइकिल पर ही दिखती है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो यह सिर्फ परिवहन का सस्ता साधन भर नहीं है बल्कि यह जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सरल, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल होने के अलावा साइकिल चलाने के महत्वपूर्ण लाभ हैं। ये व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और बहुत कुछ से लेकर हो सकते हैं। साइकिल चलाना व्यायाम का एक अच्छा रूप है। यह पर्यावरण के अनुकूल साधन है।साइकिल चलाने से स्वस्थ वजन बनाए रखने और हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, और कुछ प्रकार के कैंसर आदि जैसी कुछ स्थितियों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। हाल के दिनों में दुनिया भर में साइकिल से काम पर आने जाने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जबकि अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि आपकी साइकिल की सवारी करना फायदेमंद है, कई लोगों को यह एहसास नहीं हो सकता है कि इसका किसी के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

साइकिल चलाने से मांसपेशियों का निर्माण, वसा को खत्म करने, पैरों को मजबूत करने, रक्तचाप कम करने और सहनशक्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसकी सवारी करना, एरोबिक व्यायाम के समान है। यह नींद में सुधार कर सकता है और एक व्यक्ति के हृदय को स्वस्थ भी बना सकता है। जो लोग नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं, वे न केवल अपनी ताकत बढ़ाते हैं और मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, बल्कि अन्य खेलों में भी चोट लगने के जोखिम को कम करते हैं। कई खेलों की तरह, नियमित साइकिल चलाने से आप अपनी फिटनेस और चुस्ती फुर्ती को बनाये रखते हैं।यह एक जांचा परखा तथ्य है कि साइकिल चलाने से शारीरिक श्रम और परिश्रम होता है उसके कारण यह हमारे मानसिक दृढ़ता को भी बढाता है।

कार रखने की तुलना में साइकिल चलाना और चलाना सस्ता है। यदि किसी के पास बाइक नहीं है, तो वह इसे रांची में उपलब्ध चार्टर्ड बाइक से किराए पर ले सकता है। साइकिल के लिए किसी को पार्किंग स्थल या गैरेज की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक लोगों द्वारा साइकिल का चुनाव करने से सड़क पर टूट-फूट को कम किया जा सकता है। समूह में बाइक चलाना परिवार या दोस्तों के समूह के लिए एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने का एक शानदार तरीका है। जब कोई साइकिल चलाने जाता है तो नए, समान विचारधारा वाले दोस्तों से मिल सकता है। अगर किसी को ऐसा लगता है, तो वह एक साइक्लिन में शामिल हो सकता है

साइकिल चलाना हमें संघर्षशील होना सिखाता है, हम रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना सीख जाते हैं। यह हमें अहसास कराता है कि हम मोटर बाइक की तरह साधन संपन्न नहीं बल्कि पैरों से श्रम से चलाते हैं और छोटी मोटी समस्याओं को स्वयं ठीक करना है। इसलिये जो लोग नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं वे दूसरों की तुलना में अधिक साहसी और अधिक आत्मनिर्भर होते हैं।

RUDS
Rural Urban Development Society

Rural and Urban Development Society is supporting Humanity first in feeding the strays of Ranchi.

We are currently feeding 200+ dogs in three locations in Ranchi i.e., Ratu Raod, Baniatu & Railway Colony.

"FEEDING HUMAN'S BEST FRIEND. THEY JUST LOVE AND NOT BITE."

CONTACT US,
FOR FURTHER QUERIES & DETAILS
SWATI-9431526364

G Pay 8789398613

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।